भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

अप्रैल 2020 वर्ष 34 संख्या 3-4 मूल्य 2 रुपये

शहरों से पैदल पलायन सुर्खियों में - भारत के प्रवासी श्रमिक

देश के प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या को, केंद्र सरकार ने और सर्वोच्च न्यायालय में उसके वकील ने, खुलकर अपमानित किया है। कई राज्य सरकारें भी इसी भावना को प्रतिध्वनित कर रही हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, प्रवासी श्रमिकों पर ध्यान केंद्रित करने के एक मामले में, सरकार द्वारा *31* मार्च को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में, पैरा *41* में कहा गया है (जैसा कि द वायर में *1* अप्रैल *2020* को छपे - कोरोना वायरस बनाम मुक्त अभिव्यक्ति) "दुर्भाग्य से कुछ झूठे और भ्रामक समाचार, सोशल मीडिया संदेशों के कारण, एक दहशत पैदा हो गई थी। लगभग *4.14* करोड़ हैं जिन्होंने काम और रोजगार के उद्देश्य से पलायन किया है" और कहा कि "वर्तमान नंगे पैर प्रवास में लगभग *5* से *6* लाख हैं"। उसने पैरा *48* में आगे कहा है कि सरकार "सामाजिक-मनोवैज्ञानिक स्थानीय मुद्दे को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के मन में दहशत को संबोधित करने के लिए" गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र ही एक प्रणाली को लागू करेगी। इस तरह की रिपोर्ट और सॉलिसिटर जनरल की समान प्रस्तुतियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह सुस्त हो गया और स्वीकार किया कि इसमें कोई भी वैकल्पिक कथन नहीं है। उसने सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में विश्वास व्यक्त किया और मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की पीठ ने लिखा "शहरों में काम करने वाले बड़ी संख्या में मजदूरों का प्रवासन, तीन महीने से अधिक समय तक तालाबंदी जारी रहेगी, की फर्जी खबरों से घबराहट के कारण हुआ।" वायर ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि केंद्रीय सरकार का, पैरा *41* के माध्यम से, वास्तव में कहने का मतलब था कि असल में इतने सारे लोग नहीं चले थे और बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के चलने की खबर सोशल मीडिया द्वारा निर्मित एक मिथक थी और इससे घबराहट पैदा हो गई। जैसा भी हो, अदालत ने कहा कि इस घबराहट के कारण ही वे चले। यह घबराहट इस कारण नहीं थी कि काम रुकने की अवधि के दौरान उन्हें असमर्थित छोड़ दिया जाएगा। यह अज्ञात बीमारी को पकड़ने के डर के कारण भी नहीं थी। यह कथित रुप से सोशल मीडिया पर लॉकडाउन की अवधि को गलत पेश करने के कारण हुई थी।

सरकारें, विशेष रूप से केंद्र सरकार, यह बता रही हैं और सार्वजनिक रूप से यह कह रही हैं कि प्रवासी श्रमिक, हजारों मील की दूरी पार करने के लिए पैदल चलने पर अड़े रहे हैं, जबकि सरकार ने उनके लिए आश्रय और भोजन का प्रबंध किया हुआ है, उन्हें पैसे देने का प्रबंध किया हुआ है, जो केंद्र सरकार के आश्वासन के साथ राज्य सरकारें दे रही हैं। स्पष्ट है कि वे *25* मार्च के मंत्र, 'जहां हो वहीं रहो' का उल्लंघन करने पर आमादा थे। उन पर यह आरोप है कि जब वे इतने निश्चित थे कि वे कोरोना के समय में काम के स्थानों के पास नहीं रहना चाहते तो वे पहले ही स्थानांतरित क्यों नहीं हुए।

मजदूरों ने *22* मार्च के जनता कर्फ्यू की घोषणा के साथ जाना कि उन्हें रविवार को *14* घंटे के लिए लॉकडाउन करना होगा। उन्होंने यह भी जाना कि *21* मार्च मध्यरात्रि से *22* मार्च मध्यरात्रि तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। *22* तारीख को, जनता कर्फ्यू के बीच में, दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि *20* से अधिक लोग किसी भी स्थान पर इकट्ठा नहीं होंगे। सभी राज्यों के कैबिनेट सचिवों और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव तथा केन्द्रीय कैबिनेट सचिव की एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। उनके फैसले *23* की सुबह के समाचार पत्रों में छपे और *22* की रात को समाचार में लोगों ने देखे। उन्होंने देश में *75* जिलों की तालाबंदी घोषित की, *31* मार्च तक यात्रियों की सेवा करने वाली सभी *13,523* रेलवे ट्रेनों को रद्द कर दिया, *31* मार्च तक सभी अंतर्राज्यीय परिवहन बस सेवाओं और मेट्रो ट्रेनों के लॉकडाउन के साथ-साथ सब-वे ट्रेनों को बंद करने की घोषणा की। सम्भवतः, इसका एक कारण जो चिंता का विषय बना, यह था कि तीन कोरोना

संदिग्ध लोग *21* तारीख को लंबी दूरी की एक ट्रेन में पाए गए थे, जबकि उन्हें एकान्तवास में रहने को आदेशित किया गया था। पिछले कई हफ्तों से विदेश से उड़ान भरके आए ऐसे हजारों लोग, जिन्होंने एकान्तवास में रहने के आदेश का उल्लंघन किया था। इन *3* को सह-यात्रियों ने, इनकी कलाई पर छपी एकान्तवास की मोहर से पकड़ लिया था!

इस प्रकार, *23* तारीख की सुबह, दिल्ली व अन्य महानगरों और देश के कई हिस्सों में, श्रमिकों ने सुबह उठकर देखा कि कार्यस्थल बंद हैं, स्थानीय परिवहन, ढाबे और भोजनालय बंद हैं, आटे की कीमत में तीव्र व द्धि हुई है और कोई अंतर्राज्यीय परिवहन नहीं है। हां एक को छोड़कर। घरेलू उड़ानें *25* मार्च बुधवार तक चलती रहीं। अपनी कलाई पर छपे स्टैम्प को छिपाकर, विदेश लौटे ये लोग, इस बात से अनभिज्ञ अन्य यात्रियों के साथ अपने गंतव्य के लिए उड़ सके। *24/25* की रात को, पीएम ने तीन हफ्तों के लिए देश को 'बंद' कर दिया। पूरे देश से आई रिपोर्टों से पता चलता है कि इसके कारण बाजार में पूरी तरह घबराहट और लूट की स्थिति बन गई। बाद में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया कि आवश्यक सामान लगातार उपलब्ध रहेंगे। तब तक, देश भर में हजारों प्रवासी, जिनके लिए इस तरह का खर्च उठा पाना असंभव था, घर जाने के रास्ते तलाशने लगे।

जाहिरा तौर पर मजदूर केंद्र सरकार के आश्वासनों के बावजूद दूर का रास्ता थामने लगे थे। राज्य सरकारों द्वारा उन्हें आश्रय और भोजन दिए जाने के आश्वासन के बावजूद वे चले जा रहे थे। राज्य सरकारें कह रही हैं उन्हें कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने बस घर जाने का फैसला किया क्योंकि उनके मन में अपुष्ट डर था। प्रधानमंत्री ने *29* मार्च को, लोगों के स्वयं के भले के लिए ही 'माफी मांगी', ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो। लेकिन फिर भी वे चलते चले गए और अभी भी नहीं रुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने फर्जी खबरों की बात कही और लोगों के गुमराह होने की बात कही। क्या ऐसा ही है? या यह सच है कि लोग पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से जानते थे कि सरकारें उन्हें पूरी त्याग देंगी, भले ही वे अनगिनत मौखिक आश्वासन दे रही हैं? क्या यह भय पहले के अनुभवों और बहुत सारी चल रही प्रथाओं और सरकार की प्राथमिकताओं से खुद-ब-खुद स्थापित नही है?

क्या इसका जवाब देना इतना मुश्किल है? केंद्र सरकार का कहना है कि किसी से किराया जबरन नहीं लिया जाएगा; पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे संगठन ने किराए का भुगतान ना होने से बेदखली का सामना कर रहे वकीलों की समस्या के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही। दिल्ली में किरायेदार प्रवासी श्रमिक कहां खड़ा हो पाएगा? और अन्य शहरों में तो और मुश्किल है। केजरीवाल सरकार ने तालाबंदी के चौथे दिन आश्वासन दिया कि *4* लाख लोगों को पका हुआ भोजन मिलेगा; पहले दो दिन, उसने खुद कहा, कि *20,000* लोगों को खाना खिलाया गया। क्या यह प्रासंगिक नही है कि कुछ *3* लाख और अस्सी हजार लोग, उसके खुद के आंकड़े के अनुसार, इन दो दिनों में भूखे रह गए होंगे? भारत की वित्तमंत्री ने मुफ्त राशन देने का आश्वासन दिया; राजधानी में ही यह केवल राशन कार्ड वालों को दिया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के श्रम मंत्री ने माना है कि शहर में *2019* के ऑनलाइन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या, जो दिल्ली सरकार का *5000* रुपये का समर्थन देने का मापदंड है, वास्तविक श्रमिकों की संख्या के आसपास भी नहीं हैं (इंडियन एक्सप्रेस पेज *4*, *2* अप्रैल *2020*)। क्या केंद्र सरकार इस बात से अनजान है कि दिल्ली में प्रवासी आबादी के एक बड़े तबके के पास बीपीएल कार्ड नहीं हैं? और तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में निर्माण स्थलों पर काम कर रहे ओडिशा और झारखंड के सैकड़ों आदिवासियों की कोई गिनती ही नही है? (इस स्थिति का इफ्टू को प्रत्यक्ष ज्ञान है)। राज्य दर राज्य में, बंद कार्यस्थलों में फंसे प्रवासी कामगारों के लिए भोजन की माँग करने वाले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की मशीनरी को इन मजदूरों के लिए व्यवस्था करने को मजबूर किया है और आम तौर पर वे एक भोजन के अतिरिक्त इसका समाधान पाने में असफल रहे हैं। एक भोजन से अधिक समय तक। हरियाणा के पानीपत में, जहां प्रवासी बुनकरों और रिक्शा चालकों की एक बड़ी आबादी है, जो आमतौर पर बेहद कम मजदूरी पर काम करते हैं, इफ्टू नेताओं ने एसडीएम, एसीपी और अंत में प्रेस में जाने के साथ-साथ धरने पर जाने की धमकी दी, तब जाकर *4000* पहले से भूखे मजदूरों को, जिनके पास कोई राशन नहीं था, *31* की शाम को कुछ राहत मिली। यह राहत बासी भोजन निकला। कहीं अधिक संवेदनशील और कहीं ज्यादा खराब स्थिति का इतने सारे राज्यों में अनुभव रहा है। कभी-कभी मीडिया हाइलाइटिंग के साथ एसडीएम, डीएम पर दबाव बनाकर, कभी-कभी संघर्ष की धमकी के साथ, *30* व *31* को प्रवासियों के लिए कुछ भोजन मिल सका है, मतलब तालाबंदी के *5* वें दिन से पहले नहीं। अधिकांश प्रवासियों ने बताया कि तालाबंदी के दूसरे दिन तक भोजन और नकदी समाप्त हो गई थी। प्रवासन की उच्च दर के लिए जाने वाले कुछ राज्यों में, बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं ने एक साथ आकर, संकट में फंसे लोगों की सूचनाएं साझा कीं और दूर दराज के राज्यों के संगठनों से सम्पर्क स्थापित कर प्रशासकों और सरकार से संपर्क कर फंसे प्रवासियों के लिए भोजन और आश्रय की कोशिश की है। कई स्थानों पर नागरिक समूह, स्वयंसेवक, आरडब्ल्यूए, रोजाना बड़ी संख्या में, तालाबंदी के एक सप्ताह बाद भी भोजन करा रहे हैं, पर इसके बावजूद मांग बरकरार है। तब, वायदा की गयी सहायता कब आएगी? इस तरह की सहायता ने केवल समस्या के सिरे को ही छुआ है। द हिंदू (*2* अप्रैल *2020* का दिल्ली संस्करण) चेन्नई में कोयम्बटूर बाजार में, बंद दुकानों के

बाहर, लंबी लाइन में, बिना मास्क या शारीरिक दूरी के, बाहर बैठे श्रमिकों की एक फ्रंट पेज पर फोटो छापी है। यह शायद नकली खबर नहीं है और यह लॉकडाउन का सातवां दिन है। यहां तक कि एलडीएफ शासित केरल में, राज्य सरकार ने सभी सहायता का वायदा किया है, यहां भी कम से कम दो मामलों में कई प्रवासियों को खाना खिलाने के लिए राज्य सरकार ने कोई धनराशि मंजूर नहीं की; धन के लिए नगर पालिकाओं पर जिम्मेदारी छोड़ दी गयी, ताकि 'समर्थन' दिया जा सके और यह कहा कि ट्रेड यूनियन लॉकडाउन को 'बाधित' कर रही हैं। इस बीच, कुछ जगहों से यह स्पष्टीकरण आ रहा है कि गैर कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य सूचना है कि राशन उन्हीं को मिलेगा जिनके पास उसी राज्य का आधार कार्ड है। प्रवासियों के आधार कार्ड पर तो उनके ग ह राज्य का ही पता होगा। कई राज्यों मे आटा मिलों और चक्कियों को काम करने की अनुमति नहीं है और छोटे किराना स्टोरों से आटा गायब हो जा रहा है; वैसे भी दिल्ली में आधिकारिक तौर पर भी आटा प्रति किलो *50* रुपये से अधिक है। फिर भी सॉलिसिटर जनरल ने *31* मार्च को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लगभग *22.8* लाख प्रवासी श्रमिकों को, उनके पैत क गाँवों के लिए शहरों से पलायन के बाद, सरकार ने भोजन और आश्रय प्रदान कर दिया है। कौन सी सरकार ने और कहां? केंद्रीय ग ह सचिव भी सुनवाई में उपस्थित थे और उन्होंने बताया कि *6.6* लाख लोग देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे आश्रय घरों में हैं (स्टेट्समैन, *1* अप्रैल *2020*)। कौन सी सरकारें और कहां? - केंद्र सरकार कोई आश्रय घर नहीं चला रही है और हो सकता है कि विभिन्न राज्यों में *31* मार्च के बाद से विभिन्न जिलों में खोले गए एकान्तवास के केंद्रों में अनिवार्य तौर पर रखे गए प्रवासियों को भी इस आंकड़े के हिसाब में जोड़ लिया हो।

राजधानी में *28 - 29* की रात एक जगह एकत्रित मजदूरों क बड़ी संख्या। इस पलायन के लिए तीन राज्यों की सरकारों द्वारा मजबूरी या नियोजित रूप से की गयी सुविधाएं, (वैसे भी केंद्र की सहमति के बिना व्यवस्था नहीं हो सकती थी), इन मजदूरों को जबरन 'एकान्तवास में रखा जाना' (यह अवधारणा और यह ऊर्जा हफ्तों के लिए हवाई अड्डों पर गायब थी), केंद्र सरकार के आदेशानुसार जिलों में आश्रय शिविरों में रखा जाना और अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पूर्ण नाकेबन्दी, निःसंदेह प्रवासी श्रमिकों के पूरे मुद्दे को प्रकाश में ले आई। ऐसे में *30* के मरने की रिपोर्ट आई और इसने भी सवाल को जीवित रखा - लेकिन चिड़चिड़ाहट के रूप में, जो लोगों की परेशानी की कठोर वास्तविकता को उजागर करके द श्य को बरबाद कर देती है। किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया गया कि केंद्र सरकार प्रवासियों को भोजन देगी, जिसके लिएउसने केवल आश्रय घरों में प्रार्थना सभा आयोजित की। अब, जब *1* अप्रैल को शुरू होने वाला एनपीआर अभ्यास, जिस पर गम्भीर व व्यापक विरोध हुआ था, स्थगित कर दिया गया है, कोरोना विराधी बंदी को एक सांप्रदायिक मोड़ देने की तैयारी है। इस प्रक्रिया में मुख्यधारा की मीडिया द्वारा सहायता प्राप्त केन्द्र सरकार को प्रवासी कामगारों की समस्या को जनता के ध्यान से बाहर करने का मौका मिलेगा।

फिर भी उनका चलना जारी है। वे अधिक संख्या में बिखरे हो सकते हैं, कई को राज्य सीमाओं पर एकांतवास में डाला हुआ हो सकता है, कई ने थक कर आराम किया हो सकता है, चलती संख्या संभवतः मध्य भारत की ओर अधिक स्थानांतरित हो रही है, लेकिन वे गायब नहीं हो रहे हैं। सोशल मीडिया मंचों पर फर्जी खबरों के कारण फैली घबराहट से जो लोग इनके चलने को जोड़ रहे हैं, इनका निरंतर चलना इनके सामने कठोर निश्चितता का सबूत है। वे सभी 'नंगे पांव' नहीं हैं, लेकिन बहुत कम सामान बांध कर लंबी यात्रा के लिए चलने को तैयार हैं। ऐसा भी सुना गया है कि साइकिल और साइकिल रिक्शा वाले साइकिल चला कर घर पहुँचे हैं। लौटने वाले निश्चित रूप से अपने गांवों के सम द्ध नहीं हैं और ज्यादातर जगहों पर प्रशासन और पंचायत नेताओं से उन्हें शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी संख्या का सरकार का अनुमान कहाँ से आता है; वे अभी भी चल रहे हैं, हालांकि हो सकता है अब चलना शुरू ना कर रहे हों। उनका संदेश स्पष्ट है - वे दिन भर वेतन के लिए काम करते हैं, उनके पास कोई व्यक्तिगत बैंक बचत नहीं है, कोई सामाजिक या नौकरी की सुरक्षा नहीं है और सिर पर छत की गारंटी नहीं है। कई लोगों के लिए, महिलाएं और बच्चे घर पर हैं और ये भी कार्यस्थलों पर काम से धन हस्तांतरण पर अलग-अलग स्तर पर निर्भर थे। ये मजदूर खुद केन्द्र सरकार की इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में, उसकी ईमानदारी और क्षमता पर सवालिया निशान हैं। यह वायरस विदेश से आया था; भारत के पास बहुत समय था। *15* दिनों के एकांतवास को लागू किए बिना यात्रियों के थर्मल चेक का क्या उपयोग था? इस बात का कौन जवाब देगा, यह छोड़कर कि अन्य किसी एजेंसी या व्यक्ति ने क्या गलती की, कि विदेशियों और बाहर से लौटे भारतवासियों को हवाई अड्डों पर एकांतवास में क्यों नहीं डाला गया। किसे उत्तर देना चाहिए कि एकांतवास में 'लापता' होने के बावजूद, गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, लंबी दूरी की ट्रेनों पर, बसों और घरेलू उड़ानों पर, जैसा कि पिछले हफ्तों में बार-बार उजागर हुआ है, अभी भी अनिवार्य एकांतवास को जनवरी के अंत से ही लागू नहीं किया गया था जब यह स्पष्ट था कि यह वायरस चीन से, हवाई यात्रियों के माध्यम से फैल रहा है? ना तो प्रवासी कामगारों को अपराधी बनाने से, ना ही सांप्रदायिक जहर घोलने से, उत्तर देने से सरकार बच पाएगी। दुर्भाग्य यह है कि भारत की आम जनता इसके लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाने वाली है।

कोविड 19 – अति प्रतिक्रिया या बेतुकी और विलंबित कमजोर प्रतिक्रिया

विभिन्न टीकाकार कोविड -*19* के प्रकोप पर भारत की 'अति प्रतिक्रिया पर' प्रश्न उठा रहे हैं। उनका तर्क भारत में वायरस के भिन्न प्रक्षेपवक्र पर आधारित है। पर बहुत से ऐसे अशुभ तथ्य हैं जिन्हें नजरंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस वायरस का **RO** (**R naught** - फैलाव की गति) *2.5* है, यानी इससे संक्रमित एक व्यक्ति, *2.5* व्यक्ति को संक्रमित करेगा। यह मौसमी इन्फ्लूएंजा वायरस से बहुत अधिक है जिसका **RO** *1.1* से *1.3* के बीच है। **SARS** वायरस का **RO** *1.6* है, **H1N1** का **RO** *1.4* से *1.6* है और *1918-1920* में महामारी पैदा करने वाले इन्फ्लूएंजा वायरस का **RO** *1.4* से *2.8* तक था। **RO** अगर *1* से कम है तो उसका अर्थ है कि बीमारी खत्म हो जाएगी, *1* का मतलब है कि यह जीवित रहेगी और *1* से अधिक का मतलब यह फैलेगी। कोरोना वायरस दूसरों की तुलना में बहुत तेजी से फैलता है। हमारे समाज पर इसका प्रभाव वास्तव में भयानक हो सकता है। निवारक उपायों के आधार पर, प्रसार का **RO** बदल सकता है। सिर्फ इसलिए कि इसका प्रक्षेपवक्र भारत में दूसरे देशों की तुलना में कम रहा है, प्रसार की गति को धीमा करने के लिए एहतियाती उपायों के महत्व को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

इस वायरस के संक्रमण की तीव्र दर का एक और महत्व भी है। यह है, आप जो चाहे करें, यह फैलेगा ही और तेजी से फैलेगा। इसका प्रक्षेपवक्र अभी तक धीमा रहा है यह बात इसकी संक्रमण दरों के **ICMR** आंकड़े अच्छी तरह से दर्शाते है। ये आंकड़े केवल अतिसंवेदनशील संपर्कों की जांच से लिये गये हैं और उनमें *2.5*% लोग ही सक्रंमित पाये गये। भारत सरकार अभी तक सामान्य जनता में इसका परीक्षण नहीं कर रही है। ये आंकड़े सही प्रतीत होते हैं क्योंकि दैनिक परीक्षण की आ रही रिपोर्टों में कोई बड़ी हेरफेर करना मुश्किल होता है। लेकिन सभी महामारी विज्ञान का अनुभव इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि प्रसार निश्चित होगा और देर से नहीं, जल्द ही होगा। कोरोना के प्रसार पर भारत के लॉकडाउन का प्रभाव इसके लागू होने के *8* से *14* दिनों के बाद और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के डेटा के साथ तुलना करने से भी जाना जा सकेगा, क्योंकि इन देशों में ज्यादातर केवल हिदायतें लागू की गयी हैं।

भारत में प्रक्षेपवक्र क्यों धीमा हो गया है इसके कई कारक हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वायरस भारत के बाहर से आया है और भारत में अब तक उन सामाजिक समूहों में सीमित है जो उच्च वर्ग के हैं और हवाई यात्री हैं, शासक वर्ग के राजनेता हैं और उन जैसे हैं। जिन देशों ने रोकथाम के उपायों में देरी की है, अधिकांश यूरोप और अमेरिका, वे अब इसकी कीमत चुका रहे हैं। इटली, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में तेजी से संचरण में कौन सी विफलताएं हुई, हमें अभी भी जानना बाकी है।

भारत में प्रसार और इसका प्रभाव एक निश्चित खतरा है और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम आवश्यक हिदायतों को नकार ना दें। हमारा आनुवंशिक आधार इसके प्रति बेहतर प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है, भारत में आया वायरस का स्ट्रेन कम असरदार है, व्यापक मलेरिया संक्रमण से हमें इस वायरस से लड़ने की भी क्षमता मिलती है, और गर्मी और उमस इस वायरस को सीमित कर देती है, आदि काल्पनिक अनुमानों पर भरोसा करना बहुत जल्दबाजी और गंभीर रूप से अवैज्ञानिक होगा।

हमें याद रखना चाहिए कि भारत एक बहुत ही गरीब देश है, जिसमें बहुत खराब स्वास्थ्य और पोषण सुरक्षा की स्थिति है और देखभाल करने के लिए बहुत बड़ी आबादी है। हमें कभी भी किसी भी बड़ी आपदा के दौरान इस बात को नहीं भूलना चाहिए। कम से कम इस वायरस के हमले के दौरान, जो बहुत आसानी से फैलता है और घातक है। हमें याद रखना चाहिए कि इससे पहले हुई इसी तरह की बीमारियों में हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ है। *1918* के स्पेनिश फ्लू की एक रिपोर्ट के अनुसार 'इन्फ्लूएंजा ने *170* से *180* लाख भारतीयों की जान ली थी, जो पहले विश्व युद्ध में कुल हताहतों की संख्या से अधिक था। भारत ने इससे हुई म त्युओं का काफी बड़ा बोझ झेला था- इसने अपने *6*% आबादी को खो दिया। इनमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा थीं - अपेक्षाकृत कुपोषित, जो गैर हवादार बंद आवासों की अस्वच्छ हालातों में रहती थी और बीमार लोगों की देखभाल करती थी। ऐसा माना जाता है कि इस वैश्विक महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को संक्रमित किया और *5* से *10* करोड़ लोगों की जान ली। हमने कई महामारी त्रासदियों का सामना किया है, हैजा, टाइफाइड, चेचक, एड्स, खसरा इत्यादि। और इनका मुकाबला करने में हम बहुत विफल रहे हैं। हालांकि हम ऐसी उम्मीद नहीं करते, संभवतः इस बार का परिणाम और बदतर हो सकता है।

इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया 'बेतुकी, विलंबित और कमजोर' है।

विलंबित क्यों ?

क्योंकि हमें *22* या *24* मार्च से शुरु हुए इस लॉकडाउन से बहुत पहले, जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरु से ही, सक्रिय होकर परीक्षण और एकांतवास शुरू कर देना चाहिए

था। डब्ल्यूएचओ ने जनवरी की शुरुआत में ही खतरे की घोषणा कर दी थी।

बेतुकी क्यों ?

क्योंकि इस परिमाण के संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार, हमारी सेवाओं के बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा और हमारे सामाजिक ढांचे में अंतर्निहित 'सामाजिक दूरी' तथा 'मध्ययुगीन द ष्टिकोण' इस बड़े संकट से मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इन कारकों को संबोधित करने में विफल रही है।

भारत में आसानी से इलाज योग्य और रोके जाने वाली बीमारी से, *2018* में, तपेदिक (टीबी) के कारण *15* लाख लोगों की म त्यु हो गई और *20* लाख मलेरिया के मामले और *1000* मौतें हुईं। *2017* में *5* साल से कम उम्र के बच्चों की *10.4* लाख मौतों में से *7* लाख कुपोषण से हुई। विश्व पोषण रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा कम कद के बच्चे (*466* लाख) और कमजोर (वेस्टिड-अति कुपोषित) बच्चे (*255* लाख) हैं। भारत में पांच साल से कम उम्र वाले बच्चों में *44* प्रतिशत कुपोषित हैं, जो वायरस बीमारी समेत बीमारियों कै फैलने का बहुत बड़ा कारक है और उनके नियंत्रण को भी प्रभावित करता है। डायरिया के कारण हर साल लगभग *1.6* लाख बच्चों की मौत हो जाती है।

लॉकडाउन के बाद से, पहले से ही क्षीण स्वास्थ्य सेवाएं लगभग लकवाग्रस्त हो गई हैं। मरीज उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकारी सुविधा शायद ही आपात बीमारियों की सेवा करती है, क्योंकि वह कोरोना देखभाल से ग्रसित है। ज्यादातर मरीजों को वापस कर दिया जाता है। और लगभग पूरे निजी क्षेत्र को बंद कर दिया गया है, दोनों कारणों से, भीड़ पैदा होने के डर से और मेडिकल स्टाफ के संक्रमित होने के डर से। प्रत्येक डिस्पोजेबल पीपीई गाउन की कीमत *2200* रुपये है और इसे केवल *6* घंटे के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। कौन सी मेडिकल टीम इसका खर्च वहन कर सकती है? सरकार की कोई आपूर्ति नहीं है। एक धर्मार्थ संस्था में काम करने वाले डॉक्टरों की एक टीम ने यह कहा, 'हम सामान्य सावधानियों और उच्च जोखिम के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हर बार जब हम एक मरीज को देखते हैं तो हमें यह तय करना होता है कि हमारा जीवन अपनी सुरक्षा के लिए है या रोगी के लिए है'।

यह वह कीमत है जो समाज की स्वास्थ्य व्यवस्था के निजीकरण ने - बुनियादी ढाँचा और द ष्टिकोण दोनों से वसूली है। जैसा कि रिपोर्टों से पता चलता है, इटली, स्पेन और अमेरिका में भी निजीकरण ने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। कोरोना महामारी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के सुधार के लिए जोर से पुकार कर रही है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है।

खाद्य आपूर्ति के लिए सरकार की बहुत सारी अच्छी घोषणाएं हैं और अच्छे नागरिक मौजूद हैं, जिनकी लंबे समय तक बचे रहने की संभावना नहीं है और जो वैसे भी इतने बड़े संकट में केवल एक बहुत ही परिधीय भूमिका निभा सकते हैं। अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों को स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि राशन की अतिरिक्त आपूर्ति नहीं है, केवल नियमित आपूर्ति है। केवल अंत्योदय कार्ड धारक, जो **MNREGS** के तहत श्रम विभाग के साथ पंजीकृत हैं, को मुफ्त भोजन दिया जाएगा और बिना कार्ड वालों के लिए कोई आपूर्ति नहीं है। इसमें कमी के लिए प्रधान जिम्मेदार होंगे।

फिर हमारे सामने *8* से *10* करोड़ प्रवासी मजदूरों का गंभीर संकट है, जो घर से बहुत दूर हैं, जिन्हे बिना किसी सहारे के छोड़ दिया है, जो गैर हवादार कमरों में झुग्गियों में बैठे हुए हैं और जो वायरस को पनपने के उपजाऊ घोंसले बन सकते हैं। उन्हें पीटा गया है, रास्ते में धकेला जा रहा है, बिना सुविधा के एकांतवास में डाल दिया है, उन पर पथराव किया गया और कीटनाशकों का छिड़काव भी किया गया है। वे एकाएक निराश्रित हो गए हैं।

इन कई समस्याओं से ग्रसित देश को बंद करने से पहले किन तर्कों पर ध्यान दिया गया था ? "केवल एक दिन के कर्फ्यू" के लिए अपील की गई थी, *22* मार्च के लिए, *21* मार्च की रात को सभी ट्रेनों और बसों को अचानक रोक दिया गया था और *24* मार्च को *3* सप्ताह के लिए पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की गई थी, जिसके बढ़ाए जाने की भी धमकी मौजूद थी। जैसे ही सरकार की नींद खुली उसने एक वंचित आबादी को एकाएक निराश्रित छोड़ दिया, तैयारी के लिए भी समय नहीं दिया और जिसमें उसकी मदद करने में सरकार की कोई इच्छा नहीं थी।

कमजोर प्रतिक्रिया क्यों?

क्योंकि 'सेवा' देने वाली एकमात्र सरकारी संस्था पुलिस है। बाकी पूर्णतः पंगु हैं, लगभग एकांतवास में। शटडाउन अमल करने वाले अधिकारी, ज्यादातर 'झुंड' में बिना मास्क के हैं। यूपी के मुख्यमंत्री, हेलीकाप्टर में शहरों का दौरा कर रहे हैं और उनके चेहरे पर कभी मास्क नहीं होता है। गरीब और अविकसित देशों के लिए, शारीरिक दूरी, चेहरे पर मास्क और हाथ धोना इस बीमारी की रोकथाम के सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं और राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी खुद इसमें एक बुरा उदाहरण स्थापित कर रही हैं।

पर अब भी समय है। इच्छाशक्ति हो तो अब भी हम सुधार कर सकते हैं। यदि लॉकडाउन को सावधानी के साथ, समझदारी से अमल किया जाए, तो युवा और स्वस्थ लोगों को समाज - पुराने, बीमार, निराश्रित, की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए जुटाया जा सकता है। और यदि लॉक डाउन आपातकालीन आवाजाही के लिए सुविधाओं से लैस हो, न केवल सम द्ध लोगों के लिए (कार पास), बल्कि सभी के लिए, जैसे कि कई देशों में है।

कोरोना महामारी का मुकाबले कैसे नहीं करना चाहिए – मोदी सरकार से सीखें

अगर समस्या का एकमात्र समाधान हथौड़ी हो, तो आपको हर वस्तु कील नजर आएगी

भारत में कोरोना महामारी के हमले ने मोदी-शाह के नेतत्व में चल रहे आरएसएस-भाजपा के शासन तंत्र की गम्भीर कमियां सामने ला दी हैं। यह महामारी करोड़ों भारतवासियों की जान का खतरा बन सकती है, इसके रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदमों में, इसके नियंत्रण व प्रबंधन के लिए इन करोड़ों लाचार व वंचित भारतवासियों को शामिल किया जाना चाहिए था।

शुरुआत में कुछ तथ्य

क) कोरोना का पहला संक्रमित चीन के वुहान शहर में *17* नवम्बर *2019* को पाया गया था। दुनिया के सभी देशों को इस वायरस का जीनोम (वंशानुगत सूत्र) चीन ने भेजा। इससे इसकी जांच व रोकथाम की तैयारी का अवसर बेहतर हुआ।

ख) कोरोना यूरोप, अमेरिका तथा जापान, इरान व दक्षिण कोरिया में जल्द ही फैल गया पर यह मकर रेखा के नीचे वाले देशों में कम फैला है। इसके कारण समय के साथ सामने आएंगे। पर यह स्पष्ट है अमेरिका और यूरोप का वुहान के साथ करीबी व्यापार सम्बन्ध वहां जल्द फैलने का मुख्य कारण रहा है। यह भी स्पष्ट है अफ्रीका, लतिन अमेरिका व भारत में इसके तेजी से ना फैलने में वहां की गई बेहतर स्क्रीनिंग, सम्पर्कों का बेहतर ख्याल, लोगों का बेहतर स्वास्थ्य कतई जिम्मेदार नहीं था।

ग) चीन ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पहले वुहान शहर सील किया और फिर जिस प्रान्त में ये है, हूबी, उसे सील कर दिया और साथ में शेष सारे देश के लोगों को इसकी रोकथाम में सक्रिय किया। बन्द फैक्ट्रियों में उत्पादन बदलकर वहां मास्क सिलवाए गये, सैनेटाइज़र बनवाया गया, रेस्पिरेटर व अन्य चिकित्सकीय सामग्री बड़े पैमाने पर निर्मित की गई और इसका दूर-दराज तक वितरण कराया गया। दक्षिण कोरिया में बचाव के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की स्क्रीनिंग की गयी, खून का परीक्षण हुआ और संक्रमित रोगियों व उनके संपर्कों को एकांतवास में डालकर आम लोगों के बीच अन्य कदम उठाए गये। जापान में जब से पहले संक्रमित का पता चला, विदेश से आने वाले हर संदिग्ध व्यक्ति को एकान्तवास में डाल दिया गया।

घ) भारत में शुरु के दो महीने, *5* मार्च तक मोदी सरकार इंकार के दौर में रही और उसके मंत्रियों ने इस समस्या की गम्भीरता का मजाक तक उड़ाया। शुरु में ही उसे पर्यटकों पर रोक लगा देनी चाहिए थी, जो इस वायरस के संक्रमण के एकमात्र संवाहक हैं। उसने विदेश से आने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग व परीक्षण नहीं कराया। उसने देश के सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आगन्तुकों के लिए जांच की व एकांतवास की सुविधाएं नहीं स्थापित कीं। यह मानना ठीक होगा कि सरकार को इस घातक वायरस की गम्भीरता के बारे में और यह तथ्य कि यह अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के द्वारा ही फैलता है, जिनमें से ज्यादातर उच्च वर्ग के व बड़े अफसर होते हैं, जो ज्यादातर अनुशासित किए जाने के प्रयासों का विरोध करते हैं, काफी पहले से जानकारी थी। सरकार के लापरवाही भरे रवैये का कारण यह वर्गीय दष्टिकोण भी हो सकता है। डब्ल्यू.एच.ओ. ने दिसम्बर में इस बीमारी की गम्भीरता के बारे में चेतावनी दे दी थी।

ङ) भारत में इस बीमारी के रोकथाम के लिए सरकार की गम्भीरता केवल तब जगी जब कई पर्यटक और वीआईपी बीमार पाए गये और परीक्षण में उनके खून में कोरोना पाया गया। तब सरकार तुरंत लॉकडाउन, कर्फ्यू की घोषणाएं करने लगी, जिसमें इस कीटाणु के संक्रमण के बाद लोगों के बड़ी संख्या में मरने के प्रचार से एक भय का माहौल बनने लगा और सरकार ने लोगों पर बात न मानने और अनुशासनहीनता का दोष लगाना शुरु कर दिया। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अगर जनता कर्फ्यू नहीं अमल करेगी तो इसे हम पुलिस द्वारा अमल कराएंगे। इस 'स्वास्थ्य' सम्बन्धी भय के रोकथाम में पुलिस सबसे ज्यादा सक्रिय है, डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और खाद्य विभाग के अफसर नहीं।

च) ध्यान से गौर करें, जितने ज्यादा वीआईपी रोकथाम की हिदायतों का पालन न करते पकड़े गये, उतनी ही सख्ती आम लोगों पर लादी जाती रही है, तब भी, जब अब तक वे इसके संक्रमण के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। संसद के बारे में घोषणा की गयी कि उसे चलता हुआ दिखना चाहिए और *24* मार्च तक वह चली, वीआईपी लोगों के समारोह जारी हैं, बड़े होटल काम कर रहे हैं और पार्टियां हो रही हैं, राष्ट्रपति खुद प्रातः भोज के लिए अतिथियों को बुला रहे हैं, मध्यप्रदेश में नए मंत्रीमंडल ने शपथ ली और रामलला की पूजा *25* मार्च तक चली जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद भाग लिया - सब बिना मास्क के और बिना सामाजिक दूरी बनाए हुए।

पर आम लोगों के लिए सब बंद है, फैक्ट्री, दुकानें, अस्पताल (लगभग सब बंद हैं), यातायात, रेलगाड़ी, घरों से बाहर निकलने पर पुलिस बेरहमी से लाठी चला रही है,

वाहन सीज़ कर रही है और एफआईआर दर्ज करके लोगों को घर के अंदर ढकेल दे रही है। जब रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ने की शिकायत आने लगी तो उनकी संख्या बढ़ाने की जगह, उन्हें पूरी तरह रोक दिया गया।

छ) गांव में लोग काम के न होने, आमदनी न होने, दुकानें व अन्य सुविधाएं न होने से काफी भयभीत हैं। सबसे बुरा हाल बड़े महानगरों में रहने वाले करोड़ो प्रवासी मजदूरों का है, जो वहां से बाहर निकलकर दूर-दराज अपने गांव पहुंचने के प्रयास में हैं ताकि वे अपनी नई बेरोजगारी, गंदगी से ग्रसित और भीड़-भाड़ वाली झुग्गियों से मुक्ति पाएं, परदेस में इस फैलती हुई भयानक बीमारी व मौत के भय से मुक्त होकर घर पहुँच जाएं। ये झुग्गियां कोरोना के संक्रमण के लिए सबसे खतरनाक स्थान हैं, हालांकि इनमें रहने वाले लोग इस विशेष खतरे से उतने ही महरूम हैं, जितना कि कोरोना के संक्रमण से। यह सच है कि ये झुग्गियां ही कोरोना के फैलाव के तीसरे दौर में, सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में पहुँचने के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं और इसके बाद यह इन्हीं क्षेत्रों में स्थानिक रूप भी धारण कर सकती है (विशेष क्षेत्र में बीमारी का बना रहना)।

और फिर जेलों में भीड़ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिकता पूरी करते हुए उनकी संख्या कम करने को कहा है, पर न तो उसकी कोई तिथि तय की और न ही यह कहा कि छोटे अपराधों में गिरफ्तारियां बन्द करो। गिरफ्तारियां जारी हैं। जेलों में तो संक्रमण बाहर से ही जाएगा। यदि छोटे अपराधों में बंद कैदियों को छोड़ दिया जाता तो यह निकलने वालों और अंदर बचे कैदियों, दोनो के लिए बेहतर होता।

वैसे हवाई जहाजों को सबसे आखिर में शॅटडाउन किया गया है और निजी वाहनों को अब भी शटडाउन नहीं किया गया है।

ज) कागजों में दर्ज है कि खाना और स्वास्थ्य की सुविधाएं आपात सेवा के रूप में खुली रहेंगी और मजदूरों को पूरे माह का खर्च चलाने के लिए *1000* रुपये के पेमेन्ट की बात है। सरकार को घर तक आपूर्ति करनी है पर इसके लिए कोई ढांचा तैयार नहीं है। इस तरह की रोकथाम से दुकानों में आपूर्ति के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे और निश्चित तौर पर कमी बढ़ेगी और भय बढ़ेगा। जैसा कि इकोनॉमिक टाईम्स की एक रिपोर्ट में लिखा है "ई-व्यापार सेवा द्वारा *20* से *22* मार्च के बीच *35* फीसदी उपभोक्ता सामान नहीं प्राप्त कर पाए और *23-24* मार्च को ये *79* फीसदी हो गये।" इसी तरह दुकानों से आवश्यक वस्तुओं की खरीद में *17* फीसदी लोगों को *20* से *22* मार्च तक निराश होना पड़ा और *23-24* मार्च के बीच *32* फीसदी को। दिल्ली-नोएडा सीमा पर वाहनों की भीड़ लग गई, क्योंकि उन्हें रोका जा रहा था।

हम एक अभूतपूर्व गम्भीर दौर से गुजर रहे हैं और इसी तरह से लोगों को वंचित किया गया तो लोग अपनी खाने और इलाज की वास्तविक जरूरतों की पूर्ति के लिए बेचैन हो जाएंगे और उनकी आवश्यकता से प्रेरित उनके गुस्से का विस्फोट, कोरोना से बचने और पुलिस की हथौड़ी की मार पर भारी पड़ेगा।

झ) इस वायरस के रोकथाम के कुछ विशिष्ट पहलुओं और चिकित्सकीय हिदायतें पर गौर करना जरूरी है। यह ड्रॉपलेट (छोटी बूंद) संक्रमण से फैलता है, वायु से नहीं। इसका अर्थ है कि जो मरीज या संवाहक छींक या खांसी के द्वारा इसे वायु में पहुँचाता है वे छींक की बूंदें ही किसी दूसरे को बीमार कर सकती हैं। ये छींक की बूंदे अधिकतम *1* मीटर दूर तक फैलती हैं और वायु में यह वायरस *2* से *3* घंटे तक ही जीवित रहता है। इन बूंदों से बचने के लिए सबसे अच्छा स्थान खुली हवा है, क्योंकि खुली हवा में ये जल्दी से बह जाती हैं और खुली हवा में वायरस का घनत्व भी कम होता जाता है। ये बूंदे हाथ से, मोबाइल फोन से व अन्य वस्तुओं पर चिपक कर भी फैल सकती हैं, जिन पर ये वायरस *1 - 2* दिन तक जीवित रहता है।

एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोगों को इस वासरस से सक्रंमित होने के प्रति इतना नहीं डरना चाहिए कि एक भी अगर शरीर में पहुँच गया तो वे बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता इस बात पर निर्भर है कि यह कितने घनत्व/संख्या में शरीर में प्रवेश करता है। कम संख्या में प्रवेश करेगा तो शरीर इसका मुकाबला कर लेता है। यह वायरस उन बीमार लोगों में ज्यादा मार करता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और डायबिटीज़ में, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, दमा के रोगियों तथा सभी व द्ध लोगों में।

सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सभी वायरल संक्रमणों में व्यक्ति के स्वस्थ व पोषित होने का बड़ा महत्व है, पौष्टिक आहार, रोकथाम की प्राकृतिक क्षमता विकसित करता है।

इसकी रोकथाम में निम्न कदम उठाए जाने जरूरी हैं :

1) शारीरिक दूरी बनाए रखना, यानी आम लोगों का एक दूसरे से *1* मीटर दूर रहना और मरीज/ संदिग्ध व्यक्ति से *2* मीटर दूरी।

2) सभी लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग।

3) सभी लोगों द्वारा घर पहुँचते ही और खाना खाने से पहले साबुन से *20* सेकेन्ड तक रगड़कर हाथ धोना।

4) सभी संभावित मरीजों को एकांतवास में रखना और व द्धों को घरों के अंदर रखना।

5) एक कमरे के घरों में तथा जेलों में भीड़ कम करना।

6) पूरे समुदाय में लोगों के पोषण को दुरुस्त रखना और

7) स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना।

इस महामारी का मुकाबला करने के लिए योजना बनाते वक्त निम्न बिन्दुओं का ख्याल रखना जरूरी है :

1) लम्बी अवधि तक यह कदम उठाए जाने जरूरी हो सकते हैं, सम्भव है कुछ महीनों तक।

2) पूरे समाज को शामिल करके, न केवल प्रबुद्ध लोगों को, इसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी ताकि आम लोग इसे स्वीकार कर सकें और इसके अमल में योगदान भी कर सकें।

3) ज्यादातर लोग घनी बस्तियों और छोटे घरों में रहते हैं।

4) जब आम जीवन को शॅटडाउन कर दिया जाता है, तब हर रोजमर्रा की जरूरतों, खाना, दवा, पानी, म त्यु में, आपात सेवाओं की व्यवस्था करनी जरूरी है।

निम्न निवारक कदम उठाए जाने चाहियेः

1. स्थिति की गम्भीरता का पूर्वानुमान लगाते हुए विदेशों से आए पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था और आने वाले सभी लोगों का परीक्षण व एकांतवास की व्यवस्था फरवरी से ही, जब से वायरस यूरोप में फैला, की जानी चाहिए थी।

2. झुग्गी बस्तियों और जेलों में भीड़ कम करनी चाहिए। महानगरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को घर पहुँचने के लिए ट्रेन की सुविधा देनी चाहिए और डिब्बों में कम संख्या में लोगों को बैठाना चाहिए। घनी बस्तियों के लोगों को खाली पड़ी बिल्डिंगों व निर्माणाधीन इमारतों में अस्थायी रूप से भेज देना चाहिए। बीमार व व द्धों को घरों में रहने की हिदायत देनी चाहिए। इस दौर में समाज की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए युवाओं को गोलबंद व सक्रिय करना चाहिए। आपात स्थितियों के लिए लोगों को परिवहन की सुविधा मुफ्त में देनी चाहिये।

3. सभी गरीबों को अधिक प्रोटीन वाले खाद्यान्न, अंडे, मीट, दाल और अतिरिक्त पैसा देकर उनके पौष्टिक आहार की गारंटी करनी चाहिए। ईंधन और पानी की व्यवस्था बस्तियों में करनी चाहिये। खेतों से खाने की सामग्री और गोदामों से सामान प्राप्त कर लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और सहयोग भी।

4. मास्क, साबुन व सैनेटाइज़र के उत्पादन के लिए हर ब्लाक/गांव में ग्राम समितियों को सक्रिय करके आपात कदम उठाए जाने चाहिए। गांव के युवाओं को हर घर में इनके वितरण के लिए, हर व्यक्ति को दो मास्क और हर घर को साबुन व सैनेटाइज़र देने व घर के सभी लोगों को हाथ धोने व दूर रहने का प्रशिक्षण देना चाहिए। इन सबके उत्पादन व आपूर्ति की टीमें युद्धस्तर पर विकसित करनी चाहिए और इसमें शारीरिक दूरी तथा सामाजिक सहभागिता को बढ़ाना चाहिये।

5. अगर सामुदायिक फैलाव बढ़ गया, ये सारे कदम महीनों तक अमल करने जरूरी हो जाएंगे और बहुत सारे अस्पताल व चिकित्सकीय सुविधाओं की जरूरत होगी। अगर सरकार गम्भीर है तो उसे गांव व बस्ती के बंद स्कूल में अल्पकालिक अस्पताल बना देना चाहिए, जिनमें सुविधाएं देनी चाहिए और इसके लायक लोगों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

क्या नहीं करना चाहिए :

1. यह लाकडाउन जनता को लम्बी अवधि की बंदी के लिए तैयार किये बिना किया गया है। यह सरकार की बौखलाहट प्रदर्शित करता है, जिस सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए हों और अब उसे पता नहीं है कि क्या करे। वह अभी से डर फैला रही है जो 'अज्ञानता' के भय के रूप में और बढ़ रहा है। जिस जनमानस के पास कम सुविधाएं और साधन हैं और अब उनका रोजगार भी छिन गया और वे घर भी नहीं पहुँच पा रहे, उनमें भय बहुत ज्यादा है। अधिकारी भी, जिनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं, लोगों को घरों में ढ़केलने के अलावा भयभीत ढंग से अपने हाथों पर अल्कोहल मल रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। ऊपर बताये गये तरीकों को अपनाकर आसानी से अधिकारियों व आम लोगों को इस संघर्ष के लिए प्रेरित व गोलबंद किया जा सकता था और अब भी किया जाना चाहिए।

2. सरकार ने अपनी राजनीतिक योजना के अनुसार *22* मार्च शाम *5* बजे थाली पीटने व शंख बजाने के लिए निर्देश दिया जो उसका सामाजिक गोलबंदी का अभियान था। यह मूल रूप से लोगों के बीच 'वायरस का भूत' भगाने का एक मध्ययुगीन कदम था। बाबा रामदेव ने दिन में दो बाद सूर्य नमस्कार करने को कहा। कुछ आरएसएस के लोगों ने गौमूत्र व शाकाहारी भोजन की भी वकालत की। ये सभी कदम सरकार की विफलता के असली कारण से लोगों का ध्यान बांटने के लिए उठाए जा रहे हैं। सरकार अब भी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने, लोगों की पोषण व चिकित्सा की देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे-जैसे संकट बढ़ेगा वैसे-वैसे सरकार पिछड़ेपन के प्रचार के अपने कदमों को और बढ़ावा देगी और साथ में पुलिस दमन को भी। आखिरकार जब सरकार के पास समाधान के लिए केवल हथौड़ा ही है तो उसे जनता भी कील ही नजर आएगी, जिसे ठोकना जरूरी है।

आशीष मित्तल

चौथी बरसी पर : का. रवि की याद में

वाई.के.

इस दिन (9 मार्च) चार साल पहले हमने अपनी पार्टी का एक स्तंभ खो दिया था और क्रांतिकारी आंदोलन ने एक रोशनी का चिराग। का. रायला सुभाष चंद्र बोस (हम सभी के लिए रवि) उन विरले लोगों में से थे, जो अपनी उपस्थिति को नहीं थेपते, लेकिन उनकी अनुपस्थिति सभी द्वारा महसूस की जाती है; वे अपने स्वयं अपना ढ़िंढोरा पीटते रहने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आंदोलन में जिनके योगदान उज्ज्वल हैं। एक चमकीले तारे की तरह उसकी चमक मंद नहीं हुई है और समय की दूरी के बावजूद मंद नहीं होगी।

हालाँकि हम लगभग चार दशकों से एक ही पार्टी में थे, मुझे कामरेड रवि के बारे में करीब से जानकारी पिछले ढ़ाई दशक में हुई जब पहले वे आन्ध्र प्रदेश राज्य कमेटी के सचिव बने और बाद में केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने गए। उनके जीवन में जो संघर्ष के विभिन्न चरण शामिल हैं, उनका सरल अनुशासित जीवन, काम पर उनके द्वारा ध्यान केंद्रित करना और उनके सार्थक रवैये ने कैडर और नेताओं के बीच स्नेह, सम्मान और विस्मयपूर्ण आदर प्रेरित किया। न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में कहीं भी क्रांतिकारी आंदोलन की सफलताएँ उनके लिए अपार खुशियाँ लाती थीं, जबकि असफलताएँ उन्हें रोकने की जगह उन्हें उनके पीछे के कारणों की जाँच करने के लिए प्रेरित करती थीं। उनके विनम्र और शर्मीले व्यक्तित्व के पीछे फौलादी द ढ़ संकल्प और अबाध प्रतिबद्धता का एक क्रांतिकारी छिपा हुआ था।

का. रवि बहुत कम व्यक्तिगत जरूरतों वाले कामरेड के रूप में काम करते रहे। वह कामरेडों के सामने बहुत कम जरूरतें पेश करते थे। उन्होंव्यवस्थाने कभी धूम्रपान नहीं किया; उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कई वर्षो में चाय भी नहीं पी। मीटिंग में मदद करने वाले साथी दूसरों को चाय देते समय उसके लिए एक कप दूध लाते थे, जिसे वह बहुत संकोच के साथ स्वीकार करते और वह भी दिन में केवल एक बार। इतनी लंबी अवधि के दौरान जिसमें मैंने उनके साथ बैठकों में काफी अधिक समय बिताया, मुझे कोई भी ऐसा क्षण याद नहीं जब का रवि ने व्यवस्था के बारे में, या अपने सोने या खाने की व्यवस्था के बारे में कोई शिकायत की हो। हम इन अनुकरणीय आदतों का श्रेय दस्तों में उनके के जीवन की लम्बी अवधि को देते थे, जिसने उन्हें अपने काम में समय की अनुशासनबद्धता और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों में बहुत मितव्ययी बना दिया था।

का. रवि पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति थे। इसकी वजह यह है कि वे इस बात को गहराई से समझते थे कि पार्टी के बिना क्रांतिकारी काम में कोई सार्थक प्रगति नहीं हो सकती है। इस गहरी प्रतिबद्धता से उनके काम के दो महत्वपूर्ण पहलू सामने आए। समिति की बैठकों में वह हमेशा अपने विचारों में स्पष्ट थे और वह उन्हें स्पष्टता और बल के साथ व्यक्त करते थे। यदि वह महत्व के किसी भी मुद्दे पर अपना मन नहीं बना पाए हों, तो वह उसे बता देते थे और बाद में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मांगते थे। हालाँकि, एक बार निर्णय लेने के बाद वह इसे लागू करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। वह निर्णय को जनवादी केंद्रीयता की सच्ची भावना के साथ लागू करने के लिए सुझाव देते थे जैसे मानों यह उनकी अपनी राय रही हो। यह शब्दों में कहना आसान है लेकिन व्यवहार में अनुसरण करना इतना आसान नहीं है। पर यह कामरेड रवि के लिए आसान था क्योंकि वे खुद को पार्टी का अभिन्न अंग मानते थे और इसलिए जो कुछ भी पार्टी को प्रभावित करता वह उन्हें प्रभावित करता। कभी-कभी वे यह कहते थे कि पार्टी के निर्णयों को लागू करने के लिए उनके सख्त पालन के कारण, पार्टी के कुछ साथी जो उनकी निजी राय जानते थे उन पर व्यंग कसते थे। हालांकि इससे उन्हें कभी तकलीफ भी होती थी, इसने उन्हें परेशान नहीं किया क्योंकि वे जनवादी केंद्रीयता का पालन करना, जिसे उन्होंने पार्टी के संचालन के लिए अपरिहार्य माना, अपना परम कर्तव्य मानते थे। का. रवि पार्टी को ममजदूर वर्ग के उच्चतम संगठन के रुप में महत्व देते थे। वे मानते थे कि यह पार्टी के सर्वहारा चरित्र को भटकाना है और इससे कोई भी भटकाव पार्टी के सर्वहारा चरित्र के साथ समझौता करना होगा।

का. रवि एक टीम के रूप में काम करने की समझ रखते थे। वह हमेशा अपने पास उपलब्ध समय का अध्ययन के लिए उपयोग करते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अन्य साथियों के राजनीतिक विकास पर ध्यान देते थे और उन्हें सुझाव देते थे कि वे क्या पढ़ें और इस तरह से कामरेडों की मदद करते थे, मुश्किल पहलुओं को स्पष्टता के साथ समझाते थे, जो उनके मुद्दों के गहरे अध्ययन और स्पष्ट समझ से पैदा होती थी।

का. रवि हमेशा क्रांतिकारियों की एकता के साथ-साथ ऐसी ताकतों के साथ एकजुट कार्रवाई के लिए बहुत उत्साहित रहते थे, जो लोगों के संघर्षो को विकसित करने

में सहायक हों। उन्होंने हमेशा अन्य संगठनों के साथ एकता के प्रस्तावों का समर्थन किया। उन्होंने हमेशा साथियों को यथार्थवादी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने के लिए याद दिलाते हुए भी, अपने व्यक्तिगत विचारों को कभी भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एकता के रास्ते पर नहीं आने दिया।

का. रवि ने क्रांतिकारी कम्युनिस्ट आंदोलन की समस्याओं पर गहन चिंतन की आदत विकसित की थी। उन्होंने हमेशा क्रांतिकारी आंदोलन के रणनीतिक दिशा की अपनी द ढ़ समझ को उस ठोस स्थितियों के विस्त त अध्ययन के साथ जोड़ा जिसमें यह रणनीतिक दिशा लागू की जानी है। संक्षेप में क्रांतिकारी जन दिशा में उनका गहरा विश्वास था और वे इससे हर विचलन का विरोध करते थे। जब भी वह एक राय व्यक्त करते थे, चाहे कोई इससे सहमत हो या नहीं, वे सभी साथियों का गंभीर ध्यान आकर्षित करते थे। वह अन्य कामरेडों के विचारों को धैर्यपूर्वक सुनते थे और उन पर गहन विचार करते थे। का. रवि के साथ एक ही पार्टी में और वह भी एक ही कमेटी में काम करना एक शानदार अनुभव था। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था और मैंने क्रांतिकारी आंदोलन के उनके अनुभव से और उनके द्वारा अभ्यास किए गए संगठनात्मक तरीकों से भी बहुत कुछ सीखा।

कामरेड रवि पार्टी द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे खतरनाक कार्यों के लिए स्वयं तैयार थे। चाहे वह 80 के दशक के मध्य में गोदावरी जिलों की कठिन स्थिति थी या उत्तरी तेलंगाना के आन्दोलन को पुनः ऊर्जा देने की चुनौती हो। का. रवि ने हमेशा इनकी जिम्मेदारी स्वेच्छा से ली। यह, एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट का सबसे अच्छा गुण, उनमे बहुतायत में था।

साथियों को का. रवि के जीवन और काम से सीखना चाहिए। का० रवि को दी गयी अपनी श्रद्धांजलि में केन्द्रीय कमेटी ने कहा था, "का. रवि एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट के सबसे बेहतरीन गुणों का प्रतीक थे। उनका सादा और अनुशासित जीवन, मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ-त्से-तुंग विचारधारा के प्रति उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता, नवजनवादी क्रांति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, कड़े अनुशासन का पालन करते हुए हर किसी को साथ लेकर चलने की उनकी संगठनात्मक क्षमता, कठोर और जोखिम भरे काम करने की उनकी इच्छा, उनके हर मुश्किल को सहने और क्रांतिकारी आंदोलन के हित में हर बलिदान देने की इच्छा ने उन्हें देश के क्रांतिकारी आंदोलन के सबसे अच्छे नेताओं में से एक के रूप में खड़ा किया।" साथी इन गुणों को अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में आत्मसात करेंगे। उन्हें उनके काम और उदाहरण से बहुत कुछ सीखना है और देश में नवजनवादी क्रांति के लक्ष्य की सेवा के लिए उनसे जरूर सीखना चाहिए।

किसी भी समयावधि के लिए ऐसे गुणों का होना बहुत अच्छा है। पर इन पर लगभग पांच दशकों तक इनका अभ्यास करने, इनमें से अधिकांश कठिन व भूमिगत रूप में, वास्तव में अनुकरण के योग्य है। यहां तक कि अपने जीवन में उनका आंशिक अनुवाद भी किसी भी साथी को योग्य बना देगा। उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी तरीके से जिया।

आज जब पार्टी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है और उसके सामने अवसर भी हैं, हम उपयुक्त कार्यों को सूत्रबद्ध व अमल करने में उनके योगदान को बहुत याद करते हैं। उनका उदाहरण हमें भारत में नवजनवादी क्रांति करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

9 मार्च, 2020

पत्रिका के सभी पाठकों से अनुरोध

- *लाक डाउन के कारण पत्रिका का पुराने रुप में प्रकाशन सम्भव नहीं है। तथापि आज पाठकों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराना और भी जरूरी है। हम पत्रिका के ई-संस्करण के प्रकाशन के जरिये जहां तक संभव है इस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें आपके सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है।*
- *साथियों तक पत्रिका पहुंचाने के लिए साथी ईमेल तथा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। जो साथी इनके इस्तेमाल से परिचित न हों कार्यकर्ता उन्हें पत्रिका में प्रकाशित लेखों, रिपोर्टों तथा सामग्री से अवगत करायें।*
- *पत्रिका के लिए हमें लेख व रिपोर्ट नियमित रुप से भेजें। मौजूदा समय में इसकी जरूरत और बढ़ गयी है।*
- *पत्रिका के इस्तेमाल करने का प्रयास करें। स्वयं भी पढ़े और अधिक से अधिक लोगों को भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *पत्रिका के सहयोग के लिए राशि जमा करें।*

फिलिस्तीन पर ट्रम्प योजना : प्रारम्भ से ही शमशान मे

28 जनवरी, 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने साथ खड़े नेतन्याहू के सामने अपनी तरफ से फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को समाप्त करने के अपने कथित शांति प्रारूप की घोषणा की। उसका प्रशासन इस कथित अरब-इजरायल शांति योजना को सदी का सौदा कह रहा है। लेकिन यह अनिवार्य रूप से ट्रम्प और नेतन्याहू के बीच एक सौदा था, जो अपने देशों के शासक वर्गो के सबसे अनुदारपंथी तबकों के प्रतिनिधि हैं। इसने लंबे समय से अरब दुनिया में चल रही अमेरिकी योजना को, अब वास्तविक उद्देश्यों को बिना छिपाए, ट्रम्प द्वारा अपने परिचित अंदाज में बिगुल बजाते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। 80 पेज का दस्तावेज यह स्पष्ट करता है कि यह 'शांति योजना' नहीं है, बल्कि फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को समाप्त कर देने की योजना है।

यह योजना अमेरिकी साम्राज्यवाद और पश्चिम एशिया में इसके मुख्य स्तंभों, जियनवादी इसराइल और सउदी शाही परिवार के नेतत्व में खाड़ी के राजशाहियों का फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक नए हमले का प्रतिनिधित्व करती है। यह वह कीमत है जो क्षेत्र के अरब शाह अपने शासन की रक्षा और क्षेत्र के समद्ध पेट्रोलियम संसाधनों की लूट के लिए भुगतान करने को तैयार है। जैसे-जैसे उनके अपने देशों के लोग अधिक से अधिक बेचैन हो रहे हैं और इन पतनशील शासकों के खिलाफ उठ खड़े हो रहे हैं, वे और तेजी से अमेरिका के सैन्य बलों पर निर्भर होते जा रहे हैं। ह्वाइट हाउस में जब ट्रम्प ने इस योजना का अनावरण किया तब संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान के राजदूतों की उपस्थिति इस तथ्य को स्पष्ट कर देती है कि खाड़ी की राजशाहियां भी योजना का हिस्सा हैं। सऊदी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में बहुत कुछ पढ़ा नहीं जाना चाहिए : वह केवल दिखावे के लिए है। उन्होंने मनामा (बहरीन की राजधानी) बैठक में भाग लिया था जहाँ ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर ने इस योजना का आर्थिक हिस्सा प्रस्तुत किया था। यह योजना वास्तव में इन खाड़ी राजतंत्रों द्वारा निवेश के लिए प्रदान की गई है जो केवल यह प्रदर्शित करती है कि इस ऐतिहासिक विश्वासघात में वे भी मजबूती से शामिल हैं। इस योजना के मायने हैं कि अरबों का धन खर्च कराकर फिलिस्तीनियों की सहमति खरीद ली जाए, वे अपने राष्ट्रीय अधिकारों को छोड़ दें। ये अपने ही एजेंटों को उन्ही के पैसे से भुगतान करने का एक पसंदीदा पुराना औपनिवेशिक तरीका रहा है। यदि फिलीस्तीन अपने राष्ट्रीय अधिकारों के परिसमापन को स्वीकार कर ले, तो इसके एवज में ट्रम्प ने 50 अरब डॉलर का निवेश करने की बार-बार पेशकश की है।

इस योजना के व्यापक संदर्भों में पूरे येरुशलम को इजराइल को उपहार में देना है, फिलिस्तीन भूमि पर जबरन जियनवादी शासकों द्वारा स्थापित सभी बस्तियों को स्वीकार करना, पूरे जार्डन घाटी पर इजराइल का कब्जा करा देना, एक दूसरे से पथक फिलिस्तीनी बस्तियों की स्थापना करना, जिन्हें सुरंगों और पुलों के माध्यम से जोड़ा जाएगा, इजरायल के हाथों में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा सौंप देना और कुछ सालों तक उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर फिलिस्तीनियों को अलग राज्य का अनुदान देना है। यह केवल कुछ आवासीय क्षेत्र प्रदान करता है जहां फिलिस्तीनियों को तब तक रहने दिया जाएगा जब तक वे अच्छा व्यवहार करते रहेंगे और वह भी इजरायल के नियंत्रण में रहते हुए। इसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार फिलिस्तीनियों के वापस लौटने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है और उनका अपना रक्षा बल रखने का अधिकार भी। योजना में फिलिस्तीनियों के लिए ऐतिहासिक फिलिस्तीन की केवल 10 फीसदी भूमि छोड़ने की परिकल्पना की गई है। अच्छे व्यवहार में आतंकवाद को समाप्त करना शामिल है। इसमें फिलिस्तीन की 90 फीसदी भूमि पर यहूदी राज्य के कब्जे को मान्यता देना है और उसके खिलाफ प्रतिरोध को समाप्त करना है। इस नए राज में फिलिस्तीनी अच्छा व्यवहार करेंगे और अमेरिकी प्रशासन द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा उन्हें कुछ बन्टुस्तान मिलेंगे (नस्लीय भेदभाव के दौरान दक्षिण अफ्रीका में श्वेत शासन द्वारा एक खास अफ्रीकी जनजाति को आंशिक आत्मशासन के लिए दिया गया क्षेत्र)। बस इतना ही लट्टू लटकाया जा रहा है और इजरायल की असली योजना है कि फिलिस्तीनियों को उनकी 'वायदा की गई भूमि' से पूरी तरह से खदेड़ दे।

वास्तव में यह योजना अचानक सामने नहीं आई है। यह अनिवार्य रूप से बुश प्रशासन की योजना पर आधारित है जो अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके सहयोगियों के सशस्त्र बलों द्वारा इराक के कब्जे के बाद उभरी थी। तब इसकी बंटुस्तान योजना के रूप में आलोचना की गई थी। वास्तव में, अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों की दो राज्यों की योजना में एक पूर्ण राज्य है यानी इजरायल और एक गैर-राज्य है अर्थात् फिलिस्तीन। इसके कुछ बिंदु थे यानी फिलिस्तीन पर इजरायल के कब्जे का सत्यापन, सैन्य बलों के बिना फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण और इजरायल में अपने घरों में लौटने के लिए फिलिस्तीनियों के अधिकार का छोड़ना था, उन घरों से जहां से उन्हें बाहर निकाला गया था। सभी अमेरिकी शासनों ने इसी पर जोर दिया है। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान क्लिंटन द्वारा आयोजित कैंप डेविड वार्ता भी इसी मुद्दे पर टूट गई थी। ओस्लो समझौते में इसे भविष्य की बातचीत के लिए छोड़ दिया गया था। ओस्लो समझौतों के समय से ही एक गलत उम्मीद बन गयी थी कि गाजा पट्टी और पश्चिमी तट में एक फिलिस्तीनी राज्य बनाया जाएगा, हालांकि पूरी बात अस्पष्ट थी और कोई भी विवरण नहीं दिया गया था। ट्रम्प की योजना के साथ अब

लंबे समय से इंक्यूबेटर में पड़ी ओस्लो प्रक्रिया मर चुकी है। इस बार इसकी म त्यु की खबर कोई अतिश्योक्ति नहीं है।

अब ट्रम्प को अमेरिकी योजनाओं पर पर्दा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ट्रम्प के अपने द ष्टिकोण के अलावा, अरब शासकों और तानाशाहों, जिन्हें अमेरिकी सेना की अधिकाधिक आवश्यकता है, की मिलीभगत भी बहुत आवश्यक है, और इसमें इस्राइल के सशस्त्र बल के अपने ही लोगों से अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करने का बिन्दु भी हो सकता है। पूरी अरब दुनिया भारी उथल-पुथल में है, क्योंकि अरब जनता में असंतोष बढ़ रहा है, साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच बढ़ते अंतर्विरोधों के बावजूद इस क्षेत्र में अधिक सैनिक भेजने की अमेरिका की अनिच्छा बनी हुई है तथा इसके प्रतिबिंब के रूप में क्षेत्र के देशों की मुखरता बढ़ रही है। ईरान और अब तुर्की को इन खाड़ी राजशाहियों द्वारा अस्तित्व के खतरों के रूप में देखा जा रहा है। लोकतंत्र और मानव अधिकारों के बिल्ले उनकी योजना पर थोपे नहीं जा सकते हैं। इसलिए, ट्रम्प ने इन बिल्लों को, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद के औजार रहे हैं और पश्चिमी ताकतें अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए इनका प्रयोग करती रही हैं, लंबे समय से त्याग दिया है।

खाड़ी राजशाहियों के अलावा, ट्रम्प योजना को अमेरिकी सहयोगियों द्वारा भी समर्थन मिला है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक प्रमुख नेता, नैन्सी पेलोसी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि "बातचीत के लिए एक आधार प्रतीत होता है"। बोरिस जॉनसन सरकार ने इस व्यंगचित्र जैसी योजना को 'गंभीर प्रस्ताव' बताया है। प्रारंभ में रूस ने योजना को 'शांति पर हमला कहा', लेकिन नेतन्याहू द्वारा पुतिन से बातचीत के बाद रूसी आलोचना बहुत अधिक हल्की हो गई है। रूस मध्य पूर्व में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहेगा और उसमें चाहेगा कि इजरायल भी उसके पक्ष में हो। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता ने "यूरोपीय संघ की स्थापित स्थिति और एक द ढ़ और व्यवहार्य दो - राज्य समाधान के लिए अपनी द ढ़ और एकजुट प्रतिबद्धता का उल्लेख किया, जो फिलिस्तीनियों और इजरायल दोनों की वैध आकांक्षाओं को ध्यान में रखता है, सभी प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत मापदंडों का सम्मान करता है"। प्रवक्ता ने योजना पर विशिष्ट टिप्पणी देने`से परहेज किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने भी इसी तरह की टिप्पणी की। क्षेत्रीय शक्तियों, ईरान और तुर्की ने हालांकि, योजना की निंदा की। *1* फरवरी को आयोजित अरब समिति और कुछ दिनों के बाद **OIC** ने योजना को अस्वीकार कर दिया है, हालांकि इन दोनों मंचों के मुख्य प्रायोजक योजना के एक पक्ष हैं। यहां तक पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों के शासक हलकों की सम्मानित पत्रिका विदेश नीति (फॉरेन पॉलिसी) ने टिप्पणी की है कि यह योजना 'एक बहुत अधिक कपटी कार्यक्रम है जिसे एक वास्तविक दो-राज्य समाधान को दूर करने और इजरायल के कब्जे व दखल को स्थायी करते हुए वास्तव में एक राज्य की वास्तविकता के लिए तैयार किया गया है'।

हालांकि ट्रम्प योजना प्रारम्भ से ही शमशान में है, लेकिन यह फिलिस्तीनियों के सामने आने वाली स्थिति की बढ़ती गंभीरता को दर्शाता है। वे एक राष्ट्र के रूप में एक अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों पर और पिछले लगभग एक सदी से, विशेष रूप से *1948* के बाद से हो रहे संघर्ष पर घातक हमले का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा वे अरब राज्यों के शासकों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं जो सत्ता में अपने अस्तित्व के लिए इनके अधिकारों का सौदा रहे हैं। दूसरी ओर, बल का संतुलन विशेष रूप से इस द्वैधता को देखते हुए उनके खिलाफ बना हुआ है। यह बार-बार दोहरायी जाने वाली उक्ति है कि फिलिस्तीन की मुक्ति का रास्ता अरब की राजधानियों से होकर गुजरता है। कोई इसे और भी अधिक इंगित कर सकता है कि यह मुख्य रूप से रियाद से होकर गुजरता है।

संयुक्त राष्ट्र भी फिलिस्तीनियों की सहायता के लिए नहीं आएगा। जहां तक फिलिस्तीनियों के अधिकारों का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित रहे हैं, जबकि यह संयुक्त राष्ट्र ही था जिसने उनकी राष्ट्रीय स्वाधीनता के सवाल पर इस योजना को अधिकृत किया था। पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा समर्थित जियनवादी शासकों ने पेट्रोलियम सम द्ध क्षेत्र के वर्चस्व की चाह में, संयुक्त राष्ट्र के जनादेश का इस्तेमाल और त्याग दोनो किया है - उनका इस्तेमाल अपने राज्य की स्थापना के लिए किया और फिलिस्तीनियों के अधिकारों की अवहेलना के लिए उन्हें त्याग दिया। संयुक्त राष्ट्र अपने सबसे शक्तिशाली सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने में शक्तिहीन है। अन्य साम्राज्यवादी देश भी कुछ उचित बयान दे सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वे इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के इच्छुक हैं और अमेरिकी साम्राज्यवाद, इजराइल और खाड़ी राजशाही जैसी शक्तिशाली ताकतों का विरोध करना पसंद नहीं करेंगे।

फिलिस्तीनियों को अपने स्वयं के संघर्ष पर निर्भर रहना होगा और उनके विश्वसनीय सहयोगी के रूप में केवल क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक ताकतें खड़ी होंगी। हालाँकि दुनिया के लोग फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं और इसके लिए उसके संघर्ष का समर्थन करते रहे हैं और कर रहे हैं परन्तु फिलिस्तीनियों का सामना सबसे क्रूर दुश्मनों से है जो न केवल उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को दबाना चाहते हैं, बल्कि वे उनकी पारंपरिक भूमि पर रहने के अधिकार को ही समाप्त कर देना चाहते हैं। फिलस्तीनी भूमि पर बसाई जा रहीं यहूदी बस्तियों के खिलाफ पश्चिमी देशों में आंदोलन बढ़ रहा है। पर साम्राज्यवादी देशों की सरकारों द्वारा इसे गैरकानूनी घोषित कर दबाया जा रहा है। हालांकि, फिलिस्तीनी लोगों का संघर्ष निर्णायक भूमिका निभाएगा, साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच बढ़ते अंतर्विरोधों से उसे मदद मिलेगी।

लाक डाउन या नाक डाउन (धाराशायी)

मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि भारत करोना के सामुदायिक प्रसार के दौर में है या नहीं क्योंकि यदि नहीं भी है तो बहुत जल्द पहुंच जाएगा। पहले दिन से ही यह स्पष्ट है कि भारत में करोना के नियंत्रण के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन किया जाना सही नही है। उसकी जनसांख्यिकी, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका सामाजिक पिछड़ापन और इस सब से ज्यादा उसके शासन का पिछड़ा रवैया, जवाबदेही का अभाव और दमन इसके अनुकूल नही है। मेरा संदर्भ केवल मोदी शासन से कतई नहीं है।

सम्पूर्ण लॉकडाउन अमल हो ही नहीं सकता था। लोग भूखे हैं, अभावग्रस्त हैं, करोना से डरे हुए हैं और अपने घरों से दूर असुरक्षा के हाल में रह रहे हैं। उनकी समस्याएं और भय रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत अपने लोगों को खाना नहीं खिला पा रहा है, वह संदिग्ध लोगों का ना ढूंढ पा रहा है ना उनकी जांच कर पा रहा है, ना ही वह समाज भर में जांच करा पा रहा है, न ही वह लोगों का सही से इलाज करा पा रहा है। लोगों का भय कैसे कम होगा?

व्यवहारिक बात यही है कि यह एक ''नाक डाउन'' का ही रूप लेता, जो रूप साफ-साफ अब दिख रहा है और इसकी गति और तीव्रता भी बढ़ रही है। प्रदेशों की 'सीमा' को सील कर दिया गया है। अब छोटे शहरों में परचून की दुकानें व सब्जी के ठेले भी बन्द कराए जा रहे हैं। घर लौट रहे प्रवासी मजदूर इस वायरस के संवाहक होने के संदेह के दायरे में हैं। उनको अलग किया जा रहा है और उन पर हमले भी हो रहे हैं। बिना किसी सुविधा के इन्हें एकान्तवास में रखने की बात कहकर इस भावना को बढ़ाने में सरकार खुद योगदान कर रही है। राज्य तथा सत्तारूढ़ दल उन्हें अपराधी की कतार में खड़ा कर रहे हैं। आखिरकार यह वो सम्पन्न लोग नहीं हैं जिन्हें हवाई जहाज भेज कर परदेस से घर बुलाया गया था। बुलन्दशहर, उप्र में परिजनों व मित्रों ने म त व्यक्ति का अंतिम संस्कार ही नहीं किया, करोना के भय से। पर बहादुरी के साथ उसके मुस्लिम 'मित्रों' ने इस जिम्मेदारी को निभाया।

जहां शासक करोना के खतरे के प्रति फरवरी तक बेफिक्र रहे, जबकि विश्व व्यापार संगठन ने जनवरी में ही इसके खतरे की घोषणा कर दी थी, उन्होंने इस वायरस को देश में हवाई मार्ग से घुसने की खुली छूट दे रखी थी। उस समय शासक नागरिकता कानून अमल कराने में व्यस्त थे और लगातार शाहीन बाग और मंसूर पार्क के प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने में व्यस्त थे। वे नहीं समझ सके कि करोना वायरस नागरिकता की अर्जी नहीं देगा। वह घुस आएगा। अब, जब उन्होंने इसके खतरे का इस्तेमाल करके इन दोनों स्थानों से प्रदर्शकारियों को जबरन 'लॉक आउट' कर दिया है, अब वे सारे देशवसियों के साथ ऐसा ही कर रहे हैं।

जहां तक माननीय प्रधानमंत्री की बात है, तो जनता को गुमराह करने के लिए नौटंकी का इस्तेमाल करने में महारत प्राप्त किसी भी व्यक्ति का इससे ज्यादा दयनीय प्रदर्शन नहीं हो सकता। *20* मार्च को वह भावुक आवाज में अपील कर रहे थे कि ''केवल एक ही दिन का सवाल है, इसे अमल करो'' और अब, इसे *21* दिनों तक बंदी जारी करने के बाद वे कह रहे हैं कि ''मेरे पास आपकी जान बचाने का और कोई तरीका नही है''। इस 'मेरे पास' को बड़े अक्षरों में लिखना चाहिये। वे अज्ञानता और बेवकूफी की महारत प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें विश्व 'प्रभुत्व' के लिए उनका एक ही प्रतिद्वंदी है, ट्रम्प।

व्यवहारिकता उनकी ताकत नहीं रही है। जितनी ज्यादा संख्या में लोग लौट रहे है, उतनी ज्यादा द ढ़ता के साथ वे नॉकडाउन के आदेश दे रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, कई लाख, कई शहरो में। भारत में झोपड़ पट्टियों में रहने वाले लोगों की संख्या करीब *8* करोड़ है। जो प्रवासी मजदूर व परिवार तत्काल प्रभावित हैं, वे जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं, वे करीब *2* करोड़ हैं और दीर्घावधि में जिन पर असर पड़ेगा, वे करीब और *4* से *6* करोड़ हैं। तो यह सवाल कुछ लाख का भी नही है, हजारों की बात छोड़ें। ये भूखे हैं, इनके मन में प्रश्न हैं, बेहद थके हुए हैं, प्रतिबंधों से भयानक भयभीत हैं और कानून का पालन कराने वालों के प्रति बेहद गुस्से में हैं। यह सम्भव है कि हम अब इस बात की प्रतीक्षा में हों, कि पुलिसकर्मी भी थक जाएं और हम फिर बंटवारे से भी भयानक मंजर देखें।

सरकारी योजना पर इस तीखी टिप्पणी का वैज्ञानिक आधार क्या है? भारत की झोपड़पट्टियां इस वायरस के प्रसार के सबसे उर्वर क्षेत्र हैं - जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बंद इलाके हैं। इनकी तुलना में गांव बहुत खुले हैं जहां बहती हवा वायरस के घनत्व को हल्का कर देती है। दूसरा उर्वर क्षेत्र है जेल, जहां बिना करोना को चेक या टेस्ट किये आज भी नये कैदी बाहर से भेजे जा रहे हैं। सरकार चाहें कितने ही इंकार की अवस्था में रहे, घर लौटने का पलायन बढ़ता ही जाएगा। बस्तियों में भीड़-भाड़ वायरस में व द्धि का सम द्ध आधार है, इन्हें खाली कराना प्राथमिकता में होना चाहिये। सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिये थी। पर उसका आदेश यही है, 'जहां हो, वहीं रहो'।

लोगों को खाना खिलाने और इलाज कराने की सरकार की मशीनरी बहुत कमजोर है। सरकार को यह जानकारी भी होनी चाहिये थी। गांव से, अभी से ही भूख और बीमारी की शिकायतें जोर पकड़ रही हैं। यह स्थिति देश भर में एक जनपक्षधर सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की जरूरत की ओर, बिना निजी क्षेत्र को शामिल किये, ध्यान आकर्षित करती है।

जो किया जाना चाहिये था वह लॉकडाउन नहीं, प्रसार की गति को मंदा करने का प्रयास था। यह तभी सम्भव था जब बुजुर्गों को और बीमार लोगों को घरों में रखा जाता और युवाओं को काम पर लगाकर सारे काम पूरे कराए जाते। यह अवसर हमने खो दिया। पर यह अवसर हमारे पास अब भी है, अगर सरकार सुनना चाहे। तब निम्न कदम उठाना अच्छा होगा।

1. एक मीटर की शारीरिक दूरी बनाए रखना और बीमार लोगों से *2* मीटर की। सामाजिक दूरी नहीं, सामाजिक बंधुत्व को बढ़ाना।

2. सभी लोग मास्क पहनें।

3. घरों मे घुसते समय, खाना खाने से पहले, ढंग से साबुन से *20* सेकेन्ड तक हाथ मल कर धोना।

4. व द्धों और बीमारी से खतरे के दायरे के लोगों को अलग रखना।

आशीष मित्तल

लाक डाउन से दिल्ली के लाखों असंगठित मज़दूरों के आवास, भोजन व करोना संक्रमण के संकट पर

दिल्ली के मुख्यमंत्री को इफ्टू की दिल्ली कमेटी का ज्ञापन

करोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र केंद्रीय सरकार ने *25* तारीख से देश भर में लाक डाउन का फरमान जारी किया। *26* तारीख को इफ्टू और *8* ट्रेड यूनियनों ने श्रम मंत्री को मेमोरेंडम दिया जिसमे शहर में कार्यरत *15* लाख असंगठित मज़दूरों के आवास, राशन, वेतन व करोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में लिखा गया। श्रम मंत्री से मुलाक़ात अन्यथा वीडियो कांफ्रेंस की गुहार लगाई किंतु उन्होंने इसे नज़रअंदाज़ किया। इस मेमोरेंडम को चीफ मिनिस्टर आफ़िस भी भेजा गया, पर जबाब भी नहीं मिला। कार्यवाही होते हुए भी नहीं दिखी।

दिल्ली और समूचा देश इस शताब्दी की सबसे बड़ी और भयंकर मानवीय त्रासदी का सामना कर रहा है। लाखों मज़दूर बीबी बच्चों के साथ शहर छोड़ कर भागने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि लाक डाउन के चौथे दिन भी उनके आवास व भोजन का बंदोबस्त सरकार ने नहीं किया है। मज़दूर सैकड़ो किलोमीटर चल रहे है क्योंकि देश की चमचमाती राजधानी, जो उनकी मेहनत से बनी है, उनके खाने और रहने का इंतज़ाम नहीं कर सकती। उन पर कोरोना संक्रमण से ज्यादा भुखमरी व अन्य बीमारियों से मरने का खतरा मंडरा रहा है।

दिल्ली सरकार ने इस ह्यूमन ट्रैजेडी से मुकाबला करने के जो घोषणा की थीं वे देर से थी व अपर्याप्त भी थी। तथा जमीनी स्तर लागू होते हुए भी नहीं दिख रहीं। हेल्पलाइन काम नहीं कर रही है या तो लगातार बिजी है या ख़राब है। *5000* रुपये की जो घोषणा निर्माण मज़दूरों के लिए की गई वह सिर्फ *47000* मज़दूरों के लिए है जबकि इनकी तादाद *2* लाख है, और यह पैसा कब मिलेगा इसकी कोई घोषणा नहीं है। स्कूलों या रैन बसेरो में रहने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया पर इनकी संख्या कम है, खचाखच भरे हुए हैं और वहां सबको दो वक्त खाना नहीं मिल रहा है। मोहल्ला क्लीनिक सब बंद हैं अतः मज़दूर और ग़रीबों के इलाज का भी कोई सिस्टम नहीं है। दिल्ली पुलिस रास्ते में जगह जगह रोक कर डंडे मर रही हे व घर भेज रही है। अतः अस्पताल जाना भी असंभव है।

इन हालातों के मद्देनज़र इफ्टू (दिल्ली कमेटी) दिल्ली सरकार से मांग करती है :

1. आवास की योजना तुरंत युद्ध स्तर पर की जाए। कई हेल्पलाइन नंबर दिये जायें जो कार्यरत हो।

2. दो वक्त के भोजन का प्रबंध तुरंत किया जाए, बच्चों के लिए दूध मुहैया कराया जाए, तमाम लोगो को मास्क और हाथ धोने के लिए साबुन दिया जाए।

3. सब मोहल्ला क्लिनिकों को तुरंत चालू कराया जाए ताकि तमाम लोग अन्य बीमारी का भी इलाज करा सकें। करोना वायरस की मुफ्त जांच करायी जाए।

4. तुरंत बसों का इंतज़ाम कराया जाए जो साफ हों, तथा जिनमें परस्पर निर्दिष्ट दूरी रखी जा सके, ताकि जो मज़दूर घर जाने को रास्ते में या बस अड्डों में ठहरे है उन्हें घर पहुँचाया जा सके।

महोदय हम आशा करते है इस ठोस परेशानियों पर सरकार तुरंत काम करेंगी। इफ्टू के साथी इस संबद्ध में मदद के लिए तैयार है अगर उन्हें बाहर निकलने के परमिट मिल जाएं।

(यह ज्ञापन इफ्टू की दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष का. अनिमेष दास तथा के महासचिव राजेश द्वारा 29.3.2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया।)

निजामुद्दीन मरकज

सांप्रदायीकरण बंद करो– कोरोना से लड़ो, लोगों से नहीं

सरकार और केंद्र सरकार का संचालन कर रही आरएसएस-भाजपा, जो कोरोना के प्रकोप के नासमझी के साथ किये गये प्रबंधन के बाद राजनीतिक एकांतवास में चली गयी थी, निजामुद्दीन मरकज में तबलीग जमात द्वारा किये गये सम्मेलन से संक्रमितों के नए मामले खुलते ही एकांतवास से बाहर आ गयी। उन्होंने तुरंत ही अपनी सांप्रदायिक चाकू को तेज करने का अवसर भांप लिया, जो कोरोना के प्रकोप के बाद से जंग खा रहा था, हालांकि उन्होंने स्थिति का उपयोग कोरोना से लड़ने के लिए कम और लोगों पर दमन करने के लिए ज्यादा किया था। इसमें शाहीनबाग व उसके जैसे कई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संचालित की जा रही विरोध सभाएं भी शामिल थी। ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना सम्बंधी सभी आदेशों का पालन करते हुए सीएए, एनपीआर, एनआरसी का विरोध कर रही थीं।

एकतरफा प्रचार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए तबलीग पर दोष मढ़कर अपनी खुद की अक्षमता, चूकों और गलत निर्णयों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। जाहिर है कि कारपोरेट नियंत्रित मीडिया से उसे विपुल समर्थन मिला है। उन्होंने उन देशों से जहां नोवल कोरोना बीमारी के फैलने की रिपोर्ट आ चुकी थी, बिना अनिवार्य सावधानी के उड़ानों के माध्यम से आगमन की अनुमति दी हुई थी और इस बात को वे छिपाना चाहते हैं। आखिरकार आने वाले लोग अमीर और रसूख वाले थे। उन्होंने यह भी चाहा कि लोगों पर थोपी गयी उन सारी कठिन परिस्थितियों को भुला दिया जाए जो उनकी बिना सोची समझी योजना और मूर्खतापूर्ण रूप से अमल किये गये लॉकडाउन के कारण मेहनतकश लोगों के गरीब तबकों पर थोपी गयी थीं। इसका शायद नोटबंदी के अलावा और कोई समानान्तर उदाहरण नहीं है। कोरोना महामारी कई देशों में फैली हुई है, पर आपने क्या कहीं भी ऐसा देखा है जहां दिल्ली, उप्र, पंजाब आदि की तरह पुलिस लोगों को बेरहमी से पीट रही है। विशेषकर क्या इतने अधिक उदाहरण किसी देश में हैं। कोरोना के फैलने के उनके द्वारा चिन्हित नए खलनायक की आड़ में इस सबको दबाने का प्रयास है।

तबलीगी जमात के सम्मेलन का आयोजन *1* से *15* मार्च तक दिल्ली में किया गया था। वहां हजारों लोग एकत्र हुए थे। पर अकेले उन्हें दोष क्यों दिया जाए? ऐसी सभाएँ कई स्थानों पर हो रही थीं। कथित तौर पर चालीस हजार तिरुपति में थे, वैष्णोदेवी और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी बड़ी संख्या में लोग थे। तब सरकार कोरोना के प्रसार को रोकने की आवश्यकता के प्रति नहीं जागी थी। उप्र के मुख्यमंत्री ने खुद तालाबंदी के दौरान रामलला के जुलूस का नेत त्व किया ! तालाबंदी की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री को *24* तारीख तक इंतजार करने की जरूरत क्या था; इसे *22* मार्च के जनता कर्फ्यू की निरंतरता में क्यों नहीं किया गया। क्या यह *23* मार्च को मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान सरकार के शपथ ग्रहण की सुविधा के लिए नहीं किया गया?

आइए, थोड़ी चर्चा हम तबलीग मण्डली पर करें। इसमें विदेशों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वीजा प्रदान किया गया। अगर वीजा पहले भी दिया गया था, तो भी इन्हें रद्द क्यों नहीं किया गया? विशेषकर उन देशों से जहां कोरोना वायरस के केस चर्चा में आ चुके थे। तथ्य यह है कि सरकार, खुद कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को कम करने के लिए दोषी है और अब अपनी विफलता को ढंकने के लिए तबलीग को बलि का बकरा बना रही है। सरकार, इस दोष में अपनी संलिप्तता की जांच से बचना चाहती है। तबलीग नेता वहां फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए बसों के परमिट के लिए अनुरोध पत्र दिखा रहे हैं, ('जहां हो, वहां रहो' की अपील) जो उन्होंने केन्द्र सरकार के अफसरों- डीसीपी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर- को तथा दिल्ली सरकार के एसडीएम और डीएम लिखे थे। ये पत्र इन अधिकारियों को प्राप्त हुए थे लेकिन इन पर अनुमति क्यों नहीं दी गयी और सरकारों द्वारा लोगों को वहां से निकालने की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। दोनो सरकारों ने इन पत्रों की प्रामाणिकता पर विवाद नहीं किया है। टीवी चैनलों ने पुलिस के एक अधिकारी का साक्षात्कार दिखाया जिसमें वह तबलीग के नेताओं से लोगों को तितर-बितर करने के लिए कह रहे हैं पर कहीं भी उन्होंने इसके लिए व्यवस्था करने की बात नहीं कही। या कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लॉकडाउन के निर्णय से अनजान थे ? वास्तव में, *21* मार्च से बसें और सड़क परिवहन पूरी तरह से सड़कों से दूर थे। दिल्ली सरकार ने *22* मार्च को 'जनता कर्फ्यू' के बाद से ही *23* की सुबह से ही प्रतिबंध को बढ़ा दिया था। *22* मार्च की सुबह *4* बजे के बाद कोई भी यात्री गाड़ी दिल्ली से नहीं गई। इन लोगों को कैसे बाहर निकलना था, इस सवाल का दोनों सरकारें उत्तर नहीं दे रही हैं। संभवतः लोगों को वहां टीवी द श्यों के लिए लंबित रखा गया था जिनमें निजामुद्दीन मरकज को सर्वव्यापी अजीत डोभाल की चौकस निगाहों के नीचे खाली कराया गया। यह अधिक कुशलता से और समय पर क्यों नहीं किया जा सका और इतने दिखावे के साथ क्यों किया

गया? नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल सरकारों ने लॉकडाउन के कारण लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं क्यों नहीं किया?

जहां तक तब लीग का सवाल है, अकेले उन पर आपराधिक मामले डालना उचित नहीं है, जबकि इतने सारे आयोजित अन्य कार्यक्रमों पर जो उसी समय हो रहे थे और बाद में भी हुए, कोई प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। दूसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिन्होंने विदेशियों के प्रवेश की अनुमति दी थी या संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने मरकज में फंसे लोगों को भेजने की सुविधा के लिए कोई कदम नहीं उठाया। प्रतीत होता है कि यह जानबूझकर किया गया सांप्रदायिक प्रतिशोध है।

जहां तबलीग नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना प्रतिशोध का कार्य है, इस गलती की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी उन पर है। वे अपने ही प्रचारकों और अनुयायियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति इतने लापरवाह क्यों थे? क्यों वे इस खतरे से बेखबर थे जबकि ऐसे संक्रमण के फैलने से पूरे समाज को खतरा है। तबलीग का वह नेता जो अब तब्लीग अनुयायियों के लिए चिकित्सा सावधानी बरतने और इलाज की वकालत कर रहा है, वही यह भी दावा करते हुए दिखाया गया है कि कोरोना आस्था रखने वालों को बीमार नहीं कर सकता है। पर कोरोना के इरादे अलग थे! आप म त्यु के बाद के जीवन को बेहतर बनाने का दावा करते हैं पर वहां लोगों को ढ़केलना क्यों जरूरी है ! एक वीडियो में एक तबलीग नेता यह दावा करते हुए दिखाई दे रहा है कि वहां कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला, जबकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग पॉजिटिव थे और कई की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने अपने परिसर के अंदर रोगियों के बारे में शिकायत क्यों नहीं की और जिस तरह से बसों के परमिट के बारे में सरकारों को लिखे गये पत्रों को पेश किया है वैसे रोगियों के बारे में सरकार अथवा अधिकारियों को दिये गये पत्र क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अपने ऊपर विश्वास रखने वाले इतने सारे लोगों को जल्दी उद्धार के लिए क्यों ढकेल रहे थे? दो मानक क्यों बनाए हुए हैं, एक विश्वास रखने वाले आम लोगों के लिए जिन्हें अपनी म त्यु की प्रतीक्षा करनी होती है, और एक आयोजकों के लिए जो एकांतवास का अभ्यास करने का दावा कर रहे हैं? हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह अच्छी तरह से जाना जाता है कि जो ये दावा करते हैं कि हर ज्ञात या यहां तक कि अज्ञात बीमारी का भी इलाज शास्त्रों में पाया जा सकता है वे अपने स्वयं के उपचार के लिए अपनी शिक्षा पर अमल न करके अस्पतालों की ओर भागते हैं। तबलीग नेताओं को स्वास्थ्य विभाग की मदद लेनी चाहिए थी और उन पीड़ितों के जीवन को बचाने और पीड़ितों से उन लोगों को संक्रमण को रोकने में सहयोग करना चाहिए जो अभी तक पीड़ित नहीं हैं।

लोगों को उनके पिछड़ेपन व अंधकारवाद के लिए दोष नहीं देना चाहिए। शासक वर्ग, जो नहीं चाहते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुद ढ़ किया जाए जैसा कि स्वास्थ्य बजट के तुच्छ आबंटन से स्पष्ट है, इसको बढ़ावा देते रहे हैं। पिछड़ेपन का प्रचार करने वाले संगठन शासक वर्गों से जुड़े हुए हैं और उनसे संरक्षण पाते हैं क्योंकि शासक वर्ग नहीं चाहते हैं कि जनता जवाबदेही की मांग करे। इन संगठनों की ताकत शासक वर्ग की राजनीति के साथ उनके जुड़ाव के कारण है न कि लोगों के पिछड़ेपन की वजह से, जिस पिछड़ेपन के बारे में बोलना इस व्यवस्था के समर्थकों व पक्षधरों का पसंदीदा शौक है। स्वास्थ्य सेवाओं का जनता से दूर होना जनता द्वारा उपचार के पुराने तरीकों को आज भी मानने का मुख्य कारण है। आम जनता बेहतर स्वास्थ्य सेवा चाहती है इसका सबूत अस्पतालों की लंबी लाइनों में देखा जा सकता है। विकल्प होते हुए पुराने तरीके इस्तेमाल करना कुछ संभ्रांत लोगों को चोचला रहा है।

लोगों को इस प्रेरित साम्प्रदायिक प्रचार को समझना चाहिए। सरकारों को भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म या प्रेरणा से जुड़ा हो और उसे अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। हर पीड़ित व्यक्ति सहयोग, सहानुभूति तथा उचित स्वास्थ्य सेवा का हकदार है। जनता के बीच जानकारी के अभाव को तथा दकियानूसी विचारों के प्रभाव को इनके खिलाफ दुराग्रह फैलाने के लिए इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

सरकारों को अपनी शिथिलता के कारण होने वाले इस वायरस के प्रसार की रोकथाम पर और संक्रमित तथा पीड़ित लोगों की देखभाल पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। हर एक पीड़ित व संक्रमित व्यक्ति सहानुभूति के साथ देखभाल का पात्र है।

सांप्रदायिक प्रचार बंद करो!

सीपीआई (एमएल) -न्यूडेमोक्रेसी

2 अप्रैल, *2020*

Pratirodh Ka Swar, Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy ***Website*** **: cpimlnd.org**

*प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-***2151/8-***ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-***110008** *से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-***110019** *से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार*